University of Lucknow | Centenary Year
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी वर्ष

University in News on 08 July 2020

AMAR UJALA MY CITY Page 1 & 5

एआईसीटीई की मंजूरी के बाद एलयू में बढ़ीं एमबीए की 60 सीटें

पुराने परिसर के लुम्बा में दाखिले के लिए होती है मारामारी, अब सीटों की संख्या 120 से बढ़कर हुई 180

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस साल से लविवि पुराने परिसर में संचालित लखनऊ यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (लुंबा) में 120 के बजाय 180 दाखिले करेगा। लविवि के सीट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अपनी मुहर लगा दी है। एआईसीटीई से मंजूरी मिलने के बाद लविवि ने इसी सत्र से बढ़ी हुई 60 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लविवि में इस समय एमबीए के दो पाठ्यक्रम संचालित हैं। पुराने परिसर स्थित लखनऊ यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में अभी तक एमबीए रेग्युलर और एमबीए सेल्फ फाइनेंस की 60-60 सीटें थीं। इन पर दाखिले के लिए हमेशा से मारामारी मचती थी। इसलिए इसमें सीट बढ़ाने की मांग उठ रही थी। प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष संजय मेधावी ने बताया कि विभाग की ओर से इसका आवेदन एआईसीटीई को भेजा गया था। एआईसीटीई ने लविवि के प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद यहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सब कुछ सही मिलने पर सेल्फ फाइनेंस की 60 सीटों की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लविवि में इसी साल से इसके दाखिले शुरू हो जाएंगे।

आईएमएस में भी एमबीए पाठ्यक्रम

लविवि में पुराने परिसर में प्रबंधन विभाग के साथ ही नए परिसर में भी एमबीए का संचालन होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में एमबीए के स्पेशलाइज पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है। आईएमएस में संचालित एमबीए एचआर की 120 सीटें, एमबीए फाइनेंस की 120 सीटें, एमबीए आईबी में 60 सीटें, एमबीए मार्केटिंग में 120 सीटें हैं।

इस बार एसईई के माध्यम से दाखिले

लविवि ने इस साल एमबीए के दाखिले राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) के माध्यम से करने का फैसला किया है। इससे पहले लविवि खुद ही आवेदन मांगता था। लविवि में बीटेक के दाखिले भी राज्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होते हैं। बाकी पाठ्यक्रमों के लिए लविवि खुद आवेदन मांगता है। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है।

लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार अब लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सहमति दे दी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कुछ वर्ष पहले तक केवल छह किमी की परिधि में था। इसके बाद उसे बढ़ाकर पूरे लखनऊ जिले तक किया गया। वहीं, विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग ने दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी का क्षेत्राधिकार सीमावर्ती चार जिलों तक करने की सहमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि इस फैसले से लखनऊ विवि की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार चाहती है कि शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने।

लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और रायबरेली तक क्षेत्राधिकार बढ़ाने को सीएम ने दी सहमति

NBT Page 1 & 2

चार और जिलों के कॉलेज भी एलयू में

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) का क्षेत्राधिकार जल्द बढ़ने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली के कॉलेजों को भी एलयू के क्षेत्राधिकार में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। अभी एलयू से 170 कॉलेज संबद्ध हैं। ▶▶ पेज 2

...तो बेहतर हो सकेगी लखनऊ विवि की आर्थिक स्थिति

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के फैसले से विवि की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की संख्या 950 है। वहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय से 170 कॉलेज संबद्ध हैं। इसके चलते दोनों ही विवि की कॉलेजों से मिलने वाली आय में काफी अंतर है। लविवि शासन के अनुदान पर निर्भर है जबकि कानपुर विवि अपनी आय से चल रहा है। इसलिए लविवि की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने और लखनऊ मंडल के कॉलेजों व उनके छात्रों की प्रशासनिक सुगमता के लिए कॉलेजों को इनके अधीन करना ठीक होगा। शासन के प्रस्ताव पर सीएम ने उन्नाव को छोड़कर मंडल के बाकी जिलों को क्षेत्राधिकार में शामिल करने को हरी झंडी दे दी है।

PIONEER Page 3

लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में होगी वृद्धि

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आने वाले दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी। सैद्धांतिक स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सहमति दे दी है। सरकार की मंशा के अनुरूप सब कुछ सही रहा तो सप्ताह के अंत तक इसके आदेश जारी हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने, छात्र हितों के संरक्षण एवं सम्बद्ध महाविद्यालयो के प्रशासनिक कार्यों के सुगम निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री की तरफ से विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लखनऊ जनपद के साथ-साथ लखनऊ मंडल के अधीन आने वाले 4 जिलों लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई शामिल होंगे। इन जिलों के शामिल होने से विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन बैठक के दौरान सुझाव दिए थे कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बनें सरकार पर बोझ न बने। माना जा रहा है कि क्षेत्राधिकार में वृद्धि विश्वविद्यालय की आय को बढ़ाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से अनुमोदन मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कवायद तेज कर दी है। इस बारे में शासन स्तर के अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया प्रोसेस में है। पूरी होने के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि वर्ष 2007-08 के दौरान की गई थी। जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन लखनऊ जनपद के महाविद्यालयों को लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन किया गया था।

i-NEXT Page 4

एलयू 4 और जिलों के डिग्री कॉलेजों को देगा संबद्धता

लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली व हरदोई के कॉलेज होंगे संबद्ध

CONCEPT PIC

LUCKNOW (7 July) : लखनऊ यूनिवर्सिटी (एलयू) के क्षेत्राधिकार में चार और जिलों को शामिल किया गया है. इसमें लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली व हरदोई के कॉलेज शामिल होंगे. इन जिलों में जितने भी डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, वह अब लविवि से संबद्ध हो जाएंगे और इन जिलों में वह नए कॉलेज खोलने के लिए मान्यता भी देगा.सीएम योगी ने एलयू के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है. जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा. यह विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2020 को 100 साल का हो जाएगा. ऐसे में इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. अभी इन चारों जिलों के डिग्री कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध हैं. दूसरी तरफ लविवि का क्षेत्राधिकार अभी सिर्फ लखनऊ जिले तक ही सीमित है और वर्तमान में यहां से लखनऊ के 176 डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं.

आर्थिक संकट से जूझ रहा एलयू

सौ साल पुराना यह विश्वविद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहा है. शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन पर ही हर साल 180 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जबकि राज्य सरकार से केवल 34 करोड़ रुपये की ही आर्थिक मदद मिलती है. इसके चलते विश्वविद्यालय के विकास में काफी कठिनाई आती है. अब चार और जिलों के कॉलेजों के संबद्ध होने से लविवि आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगा. दरअसल यूपी में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर व डॉ.भीमराव अंबेडकर विवि आगरा सहित कुछ विश्वविद्यालयों से भारी संख्या में डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं. ऐसे में अब उनका बोझ हल्का किया जाएगा.

परवान नहीं चढ़ा था प्रस्ताव

एलयू के क्षेत्राधिकार को वर्ष 2009 में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. उस समय इसे लखनऊ मंडल के ज्यादातर जिलों में संबद्धता देने की छूट दी जा रही थी, लेकिन तत्कालीन कुलपति प्रो.एएस बरार ने इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी नहीं दी थी.

DAINIK JAGRAN Page 5

लविवि अब चार और जिलों के डिग्री कॉलेजों को देगा संबद्धता

लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली व हरदोई के कॉलेज होंगे संबद्ध

राब्यू, लखनऊ : लविवि के क्षेत्राधिकार में चार और जिलों को शामिल किया गया है। इसमें लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली व हरदोई के कॉलेज शामिल होंगे। इन जिलों में जितने भी डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, वह अब लविवि से संबद्ध हो जाएंगे और इन जिलों में वह नए कॉलेज खोलने के लिए मान्यता भी देगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लविवि के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2020 को 100 साल का हो जाएगा। ऐसे में इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभी इन चारों जिलों के डिग्री कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध हैं। दूसरी तरफ लविवि का क्षेत्राधिकार अभी सिर्फ लखनऊ जिले तक ही सीमित है और वर्तमान में यहां से लखनऊ के 176 डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं।

सौ साल पुराना यह विश्वविद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन पर ही हर साल 180 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जबकि राज्य सरकार से केवल 34 करोड़ रुपये की ही आर्थिक मदद मिलती है। इसके चलते विश्वविद्यालय के विकास में काफी कठिनाई आती है। अब चार और जिलों के कॉलेजों के संबद्ध होने से लविवि आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगा। दरअसल यूपी में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर व डॉ.भीमराव अंबेडकर विवि आगरा सहित कुछ विश्वविद्यालयों से भारी संख्या में डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं। ऐसे में अब उनका बोझ हल्का किया जाएगा। लविवि के क्षेत्राधिकार को वर्ष 2009 में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।

HINDUSTAN Page 1

लविवि के दायरे में चार और जिले

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

इसके तहत इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लखनऊ जिले के साथ लखनऊ मंडल के चार जिले रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी शामिल किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय से लखनऊ विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने, छात्र हितों के संरक्षण और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों का सहजता और सुगमता के साथ निपटारे का काम हो सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। **विसं**

THE PIONEER Page 3

LU's Biochemistry department to include Covid-19 as subject

PNS ■ LUCKNOW

The Biochemistry department of Lucknow University has proposed to have Covid-19 as a part of its syllabus and also as an elective subject which can be taken up by any student from any stream. Head of the department Sudhir Mehrotra said that the Board of Studies gave its approval to the course on the July 4. He said that the syllabus has already seen massive revisions and modifications because of the choice-based credit system, approved by the Vice-Chancellor, and will be started from the new academic session.

"There is a paper in the first semester of MSc (Biochemistry) by the name of 'Clinical Biochemistry and Physiology' and I have been teaching this for the last 26 years. there is a specific unit on diseases such as hepatitis, cardiovascular, diabetes and HIV. When the revision was done last time in 2018, we included hepatitis, dengue and tuberculosis, and now we have included Covid-19 as a segment of this course," he pointed out.

He further said that they have also proposed it as an elective subject which can be taken by any student from any stream, be it Science, Commerce or Arts.

"A meeting was called by the Vice-Chancellor and teachers from other faculties suggested that it should be taken as an elective subject. The suggestion was made so that awareness could be disseminated to one and all," he said.

He said the course will now have to be approved by the Faculty Board and Academic Council before it could be included. Regarding the research on Covid-19, he said when things are back to normal, they would discuss what can be done. "Research in Biochemistry can be done only in labs and currently the faculty members are not coming on a regular basis. We will take up research after proper discussions with the teachers," he said.

RASHTRIYA SAHARA Page 9

लखनऊ विवि के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की सीएम ने दी सहमति

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी समारोह से पहले ही आत्म निर्भर बनाने की दिशा में बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले तक सीमित लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी जिलों तक करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय की जानकारी भी उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी गयी है। अभी तक इन जिलों के डिग्री कालेज छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध थे। अब लविवि का दायरा बढ़ने से जहां इन चारों जिलों के डिग्री कालेजों के निगरानी में आसानी होगी, वहीं छात्र हितों व प्रशासनिक कार्यों का सुगमता से निस्तारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों राजभवन में हुई बैठक के दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने लविवि को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया था। इस बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री डा. दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। समझा जाता है कि राज्यपाल के आत्मनिर्भर लविवि को लेकर संकेत के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी सैद्धांतिक सहमति दी है। योगी सरकार के इस निर्णय से अब लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी होने के साथ ही इन सभी जिलों के डिग्री कालेजों में छात्रों के प्रवेश को लेकर भी तेजी बढ़ जाएगी और सभी में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

अब सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी के डिग्री कालेज भी लविवि से होंगे सम्बद्ध

AMRIT VICHAR Page 3

महाविद्यालय परिसरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक

लखनऊ। राजधानी स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय ने मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अब विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अपने परिसर में शैक्षणिक कार्य से इतर किसी भी प्रकार कामर्शियल गतिविधि नहीं कर सकेंगे। इस आदेश की परिधि में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी एडेड और निजी महाविद्यालय शामिल हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के निर्देश के बाद इस संबंध में सभी महाविद्यालयों को एक सर्कुलर भेजा गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक कॉलेज परिसर में शादियों और अन्य वाणिज्यिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आयोजित समारोहों और कोचिंग संचालन पर पाबंदी रहेगी। अब इन परिसरों का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

HINDUSTAN TIMES Page 3

Govt expands work area of LU to four other districts

LUCKNOW: The state government decided to expand the work area of Lucknow University (LU) to four other districts on Tuesday.

This information was shared by the office of chief minister Yogi Adityanath.

As per the order, the LU's work area will now also include Lakhimpur Kheri, Hardoi, Sitapur and Rae Bareli districts, implying thereby that colleges in these districts can now get affiliation from the university which is in its centenary year. As of now, close to 170 colleges in the state capital are attached to LU.

"The university is yet to receive the orders from the state government regarding it. It would be too early to comment on the decision without going through the order," said vice chancellor of Lucknow University prof Alok Kumar Rai.

Meanwhile, a few city-based educationists said the order will provide an opportunity to the university to ensure quality higher education in these districts. On the other hand, a few other educationists opined that expanding work area and giving affiliation to more colleges may not necessarily lead to improvement in education.

Expressing similar views during a webinar session organised by state higher education department and national assessment and accreditation council (NAAC) at Raj Bhawan last month, governor Anandiben Patel had suggested that a university must not give affiliation to more than 300 colleges.

"Some universities give affiliation to thousands of colleges. Hence, the vice-chancellors are unable to keep tabs on the quality of education," the governor had said.

She had further said out of 20 state universities only six had NAAC rating and none had an A grade. Lucknow University holds a B grade rating in NAAC assessment. The governor had also suggested that attempts should be made to fill vacant posts of teachers to improve quality of education.